

अस्तित्व का प्रश्न हैं वन

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे पर्व और उत्सव केवल सामाजिक उल्लास के अवसर नहीं रहे बल्कि प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व के प्रतीक भी रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण और जल संकट जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला ‘वन महोत्सव’ केवल वृक्षारोपण का अभियान नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन बचाने का राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। वास्तव में वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखा जाए तो वन महोत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता क्योंकि इसका संबंध केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य से है।

भारतीय परंपरा में वनों को देवतुल्य माना गया है। वे केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े, जैव विविधता के सबसे बड़े आश्रय, नदियों के संरक्षक, जलवायु संतुलन के प्रहरी तथा करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले जुलाई 1947 में दिल्ली में चलाए गए व्यापक वृक्षारोपण अभियान ने वन महोत्सव की अवधारणा को जन्म दिया था, जिसे वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह का चयन इसलिए किया गया क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधों के जीवित रहने की संभावना सर्वाधिक रहती है। आज यह अभियान भारत के ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के दर्शन का जीवंत प्रतीक बन चुका है।

वनों की स्थिति विश्व स्तर पर चिंताजनक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पृथ्वी का केवल लगभग 31 प्रतिशत भूभाग ही वनाच्छादित है जबकि प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र अंधधुंध कटाई, औद्योगिकीकरण, खनन और अवसंरचनात्मक विकास की भेंट चढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आगामी दशकों में विश्व के अनेक वर्षावन गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे समय में भारत जैसे विशाल और जैव विविधता से समृद्ध देश की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। भारत ने हाल के वर्षों में वन संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र तथा 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। पिछले आकलन की तुलना में कुल हरित आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके बाद आते हैं। वहीं, वन घनत्व के अनुपात में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय अग्रणी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसेस्रेंस असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के आधार पर विश्व में नौवां स्थान तथा वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त हुआ है।

हालांकि इन उपलब्धियों के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि हरित आवरण में हुई वृद्धि का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक सघन वनों के बजाय खुले वनों तथा व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण हुआ है। प्राकृतिक वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि हजारों वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और जल स्रोतों का जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इसका स्थान कृत्रिम पौधरोपण कभी नहीं ले सकता। केवल पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना ही वास्तविक सफलता है।

राम मंदिर दान में चोरी का कलंक धोना आसान नहीं होगा

❏ राजेश श्रीवास्तव

24 में जब राम मंदिर भक्तों के लिए खुल गया तो लगा कि बस इस अध्याय का अंत हो गया है, लेकिन मौजूदा घटना एक बार फिर राम मंदिर को सुर्खियों में ले आया और चंपत राय इन सुर्खियों के केंद्र में आ गये। करोड़ों की आस्था, लाखों का रोज दान और इस दान पर चोरों की नजर लग गई। राम मंदिर दान में चोरी पहले इनकार की जा रही थी, लेकिन अब साबित हो गई, पैसे बरामद हो गए, एफआईआर हो गई, इस्तीफे हो गए, लेकिन राम मंदिर दान की कहानी और किस्तर अभी भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में लगे लोगों पर चोरी का आरोप लगे तो करोड़ों लोगों की आस्था, भरोसा और इत्मिनान को धक्का लगना ही था। बात सिर्फ चोरी की नहीं थी। भगवान के घर चोरी की थी और वह भी तब जब मंदिर बनाने के लिए कुर्बानियां हर स्तर पर दी गईं। अब सवाल भी हर कोने से पूछे जा रहे हैं। सवाल चोरी करने वालों पर उठे। सवाल उन पर भी उठे जो इन चोरों को खजाने तक लाए थे। इन नामों में सबसे बड़ा नाम चंपत राय बंसल का है। राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर ट्रस्ट के काम से जुड़े चंपत राय के बेकद करीबी लोग ही थे जो दान का पैसा चुरा रहे थे। उसे छुपा रहे थे, दान को खपा रहे थे, चंपत राय की नाक के नीचे ये काम हो रहा था। सबसे बड़ा और गहरा सवालिया निशान इसी चेहरे पर लगना



लाजमी था। चंपत राय पर खुद पैसा चुराने का आरोप नहीं है, लेकिन उनके खास लोगों पर इसका आरोप है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उंगलियां उठीं। उंगलियां उठीं तो चंपत राय की बरसों की बनी साख जल कर खाक हो गई। सवाल उठे कि चंपत राय की नाक के नीचे चोरी हुई या उनकी राजमंदी से, चंपत राय चालाकी से केस छुपाना चाहते थे या चोरी सामने आने पर उन्होंने लापरवाही की, क्योंकि एफआईआर जब तक हुई, तब तक राम भक्तों के दान में सेंध घर-घर की खबर और चिंता बन चुका था। राम मंदिर में चोरी की क्रोनोलाजी को समझिये। 7 जून को सपा नेता पवन पांडेय ने तो 8 जून को अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उछला तो मामले ने गामी पकड़ी। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग बार-बार कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चंपत राय ने भी यही कहा

कि कोई भी ऐसी बात इंटरनल ऑडिट में सामने नहीं आई है, जिसे उल्लेखनीय समझा जा सके। बचाव में बीजेपी भी उतरी। लड़ाई सच झूठ से ज्यादा राजनैतिक स्कोर की होती नजर आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं जिसका खमियाजा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें उठाना होगा।

जब इस तरह की खबरें आने लगीं कि सब कुछ ठीक नहीं है तो यूपी सरकार ने 14 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी बना दी, जो अगले ही दिन अयोध्या पहुंच गई और तीन दिन यानी 18 जून तक जांच करती रही। 23 जून को एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट दी, जिसकी बुनियाद पर ही 25 जून चढ़ावा चोरी में एफआईआई दर्ज की गई, जिस चोरी को चंपत राय सिरि से नकार रहे थे। उसी चोरी में केस दर्ज हो गया। इसमें नाम ऐसे लोगों का था जिन्से चंपत

पिरे रहते थे। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नु चंपत राय का ड्राइवर था। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्रा, रमा शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव हिरासत में हैं। इन सभी को सीधे या परोक्ष चंपत राय की सिफारिश पर ही राम मंदिर में नौकरी मिली थी। ये सब रामभक्तों से मिलने वाला चंदा गिनेने का काम करते थे। चोरी यहीं की जाती थी। इसी के चलते चंपत राय विवादों में हैं। राम मंदिर में दान की चोरी, सिर्फ हाथ की सफाई थी या एक संगठित अपराध।

जांच और राजनीति इसी बात के इर्द-गिर्द है कि कैसे केमिस्ट्री का एक टीचर राम मंदिर केस का रिकॉर्ड कीपर बन गया। बिजनौर के धामपुर में आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर चंपत राय बंसल को 1977 में

गिरफ्तार किया गया था लेकिन तब इमरजेंसी के आंदोलन की वजह से। वह दूसरे संघ कार्यकर्ताओं की तरह 18 महीने जेल में रहे। जब चंपत इमरजेंसी के बाद रिहा हुए। विश्व हिंदू परिषद में चले गए जहां वो वीएचपी के अध्यक्ष अशोक सिधलत के करीब आ गए। चंपत को राम जनभूमि मंदिर आंदोलन के लिए अवध इलाके में युवाओं को तैयार करने का काम दिया गया। चंपत को अयोध्या की हर गली, हर दलील और

तारीख मुंह जबानी याद थी और ये तब और अहम हो गया जब मामला तेज से अदालतों में चलने लगा। वकील तारीखों और डाटा के लिए चंपत राय की मदद लेने लगे। चंपत को नाम मिल गया, राम लला के रिकॉर्ड कीपर का।

बीजेपी ने जब राम मंदिर आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया तो चंपत बीजेपी की एक नहीं कई पीढ़ियों के नेताओं के करीब आ गए। विवादित ढांचा 6 दिसंबर, 1992 को गिरा तो चंपत का नाम साजिशकर्ताओं में शामिल किया गया, लेकिन सितंबर 2020 को सीबीआई अदालत ने उनके समेत सभी नेताओं को बरी कर दिया। चंपत अयोध्या के कार सेवकपुरम में ही रह कर ट्रस्ट का काम देख रहे थे। आरोप लगाया गया है कि इस दौरान उन्होंने मनमर्जी से लोगों को नौकरियां दीं जिनमें से कुछ लोगों ने लोगों के दान पर हाथ साफ कर दिया। चंपत ने शुरुआत में ही इस विवाद को दबाने की कोशिश की।

बीजेपी के विरोधियों को ये केस विधानसभा चुनाव से एक साल पहले किसी सुनहरे मौके जैसा लग रहा है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी और काँग्रेस को, इन दोनों पार्टियों को राम मंदिर और हिंदू राजनीति के मुद्दों पर अरबहज ही होना पड़ता है, लेकिन अब जैसे उन्हें बीजेपी पर

खराब संबंधों के लिए क्या भारत भी दोषी है? अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो भारत के हर नेतृत्व ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, लेकिन उसे इस काम में कोई सफलता नहीं मिली है। पाकिस्तान ने कभी भी भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व नहीं दिया है, बल्कि वह हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में कठपुतली बना रहा। पहले वह अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को धमकाया करता था और अब वह चीन की गोद में बैठकर भारत को हड़काने की कोशिश करता है। अब भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है, जिस पर किसी की धमकी का कोई असर नहीं होता, इसलिए अब पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत चाहता है।

पत्र लिखने वालों की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाए तो भी इसके पीछे पाकिस्तानी रणनीतिक चाल दिखाई देती है। इस पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि पाकिस्तान को अपनी आतंकवाद की नीति को छोड़ देना चाहिए। क्या पत्र लिखने वाले नहीं जानते कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आतंकवाद के कारण ही बिगड़ गए हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दे। देखा जाए तो रिश्ते सुधरने के लिए बातचीत जरूरी है, लेकिन बातचीत शुरू करने के लिए भारत ने आतंकवाद रोकने की शर्त रखी हुई है। क्या भारत की सोच गलत है, इसका जवाब पत्र नहीं देता।

पत्र लिखने वाले चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध पूरी तरह से सामान्य हो जाएं । पाकिस्तान की तरफ से पत्र लिखने वालों को छोड़ दिया जाए तो भारत से पत्र लिखने वाले आतंकवाद के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उन्हें अपने देश के हितों को देखना चाहिए था, इसके बाद इस पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए थे। भारत के पक्ष को समझे बिना प्रधानमंत्री को पत्र लिखना क्या उचित है? दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो जाते हैं तो दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। कितनी अजीब बात है कि जिसे बातचीत की ज्यादा जरूरत है, वही अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। पहलनाम हमले से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी जनरल मुनिर ने कहा था कि हिन्दू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं और भारत हमारा शत्रु राष्ट्र है। आज पाकिस्तान में एक तरह से मुनिर का शासन चल रहा है, ऐसे में दोनों देशों के संबंध कैसे सुधर सकते हैं।

वास्तव में पत्र लिखने वाले समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है उसे नहीं जानते। दूसरे शब्दों में कहें तो जानते सब कुछ हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते। जब तक पाकिस्तान की सच्चाई सामने नहीं लाई जाती, तब तक ऐसे पत्र लिखने का कोई फायदा नहीं है।

.....

आत्मबोध

मौत के बाद कर्ज का हिसाब

कई लोग यह मान लेते हैं कि इनसान की जिंदगी खत्म होने के साथ उसके सारे हिसाब-किताब भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ ‘गरुड़ पुराण’ में इस विषय को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा गया है। इसमें बताया गया है कि कर्ज केवल पैसे का लेन-देन नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्म ऋण भी है, जिसका असर मृत्यु के बाद भी आत्मा पर पड़ सकता है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का धन लौटाए बिना इस दुनिया से चला जाता है, तो उसे परलोक में अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि शास्त्र जीवन में ईमानदारी से अपने दायित्व पूरे करने की सीख देते हैं।

गरुड़ पुराण के अनुसार किसी का धन लेकर उसे वापस न करना केवल आर्थिक गलती नहीं, बल्कि धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना भी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर उधार नहीं लौटाता, तो उसका यह कर्म मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। धर्मग्रंथों में कहा गया है कि हर इनसान अपने कर्मों का फल जरूर प्राप्त करता है और ऋण भी उसी कर्म का एक हिस्सा माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद समुद्रतट ऐसी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यदि व्यक्ति ने दूसरों का धन दबाया हो और उसे लौटाने का प्रयास भी न किया हो, तो रास्ते में उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में वैतरणी का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी अत्यंत भयावह होती है, जिसमें खून, मवाद और हड्डियों का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि कर्ज न चुकाने वाली आत्मा को इस नदी को पार करते समय असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। यह वर्णन लोगों को अपने कर्मे के प्रति सजग रहने का संदेश देता है।

अगले जन्म में भी चुकाना पड़ सकता है ऋण

गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म की अवधारणा का भी जिक्र मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति का ऋण अधूरा रह जाता है, तो अगले जन्म में उसे उसका फल भोगना पड़ सकता है। (जारी)

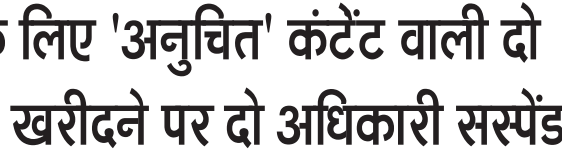
पीआरजीआई/आरएनआई पंजीयन संख्या : 52413/1991 (टाइटल कोड : JHAHIN00860),पोस्टल रजिस्ट्रेशन संख्या : RN/260/2020-22. अध्यक्ष व प्रधान संपादक: बलबीर दत्त. दत्त आउटरीच प्रॉब्लेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक रोहित दत्त" द्वारा 4/A, तारा टावर, होटल महाराजा के सामने, रडियम रोड, कवहरा चौक, रांची – 834001 से प्रकाशित तथा एसएच प्रिंटर्स प्रॉब्लेट लिमिटेड, टेंडर गलीवा के समीप, काटीटांड, रातू, रांची – 835222 से मुद्रित. फोन नंबर: 0651 2361181, 0651 2361182. ईमेल: contact@deshpran.in ("पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार).



मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की सुरंग का काम शुरू

6,700 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू से रवाना

तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान-गौरी स्प्रेट



मप्र के शिवपुरी में डिफेंस प्लांट का हुआ शिलान्यास

**डॉ. श्यामा प्रसाद
एकता और प्रगति के**

खबरकोना

गुवाहाटी, 05 जुलाई : भारत अपना ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 6-7 जुलाई को गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संरचनात्मक निरंतरता का सुनिश्चित करना तथा मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के बीच अपरिभाषित स्तर पर सहयोग को और बढ़ावा देना है। वैश्विक मादक पदार्थ तस्करी को परिश्रय फिल्टर कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ता है। सिंथेटिक ड्रग्स, न साइकोएक्टिव सस्पेंस (एनपीएस), डार्कनेट के माध्यम से होना वाली तस्करी तथा क्रिप्टोकॉर्सी आधारित वित्तीय लोन-देन जैसे प्रवृत्तियों ने जटिल अंतरराष्ट्रीय चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी : भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित जीवन

इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं, जब किसी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। डॉ. मुखर्जी का बलिदान हमें ऐसा ही था। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि डॉ. मुखर्जी ने उच्च देशप्रेम के लिए अपना बलिदान देया, जिस पर उन्हें पूरा विश्वास था। दशकों बाद, साल 2019 में आर्टिफिशल 370 और 35(अ) का खंडाजा जाना उनके प्रति सच्चा प्रह्वंजलि थी।

डॉ. मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्रहित और भारतीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके लिए उन्होंने नजबत संस्थानों का निर्माण किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, जहाँ से समकाल की सोच से काफ़ी आगे की युवा कला विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा कुलपति बने।